(d) and (e) Tenders were invited from the Indian companies with a view to provide Cellular Mobile Telephone Service, which is cableless telephone system, initially in Bombay, Delhi, Calcutta and Madras on a licence basis. 8 bidders, two in each city, were provisionally selected. Some of the unsuccessful bidders filed a civil writ petition in the High Court of Delhi. The judgement in the case has since been delivered and is under study.

(f) Does not arise.

बंगलौर में तार-रहित टेलीफोन प्रणाली

2548. **श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे** की : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बंगलौर में तार-रहित टेलीफोन प्रणाली की शुरुआत की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार इस तरह की प्रणाली देश के अन्य नगरों में भी प्रारम्भ करने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न हीं उठता ।

(ग) और (घ) आरंभ में बंबई, दिल्ली कलकत्ता और मद्रास में लाइसेंस आधार पर सेल्यूलर सचल टेलीफोन सेवा, जो केबल रहित टेलीफोन प्रणाली है, प्रदान करने की दृष्टि से भारतीय कंपनियों से निविदायें मांगी गई थी । 8 बोलीदाताओं को, अर्थात प्रत्येक शहर से दो-दो को अंनतिम रूप से चुना गया था । कुछ असफल बोलीदाताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट याचिका दायर की है । इस मामले में फैसला सुना दिया गया है जिसका अध्ययन किया जा रहा है । आठवीं योजना के दौरान बंगलौर सहित देश के अन्य बड़े शहरों में भी सेल्यूलर सचल प्रणाली प्रदान करने की योजना है ।

उपभोक्ता टेलीफोनों पर फैक्स प्रणाली के लगाए जाने के लिए शुल्क

2549. **श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन उपभोक्ताओं को अपने-अपने टेलीफोनों पर फैक्स प्रणाली लगाने के लिए 3000/- रुपये के वार्षिक शुल्क का भुगतान करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस पर प्रभारित सालाना शुल्क के कारण फैक्स के उपभोक्ताओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो रही है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ टेलीफोन उपभोक्ता अपने टेलीफोनों पर अवैध रूप से फैक्स प्रणाली लगाए हुए हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार टेलीफोन राजस्व में वृद्धि करने के लिए फैक्स सुविधा निःशुल्क देने का विचार रखती है ;

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । फैक्स उपकरण वाले उपभोक्ताओं की संख्या में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है ।

(ग) से (च) : निर्धारित लाइसेंस शुल्क अदा किये बगैर टेलीफोन लाइनों पर फैक्स के गैर कानूनी इस्तेमाल की घटनाएं विभाग के ध्यान में आती रहती हैं। ऐसे मामलों में, संबंधित उपभोक्ताओं के विरुद्ध भारतीय तार अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। लाइसेंस शुल्क समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि (I) लाइसेंस शुदा फैक्स प्रयोगकर्त्ताओं की संख्या में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है (II) लाइसेंस शुल्क, फैक्स मशीन की लागत की तुलना में काफी छोटी राशि है।

अनुरक्षण और प्रचालन, अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

2550. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को संचार प्रणाली के क्षेत्रीय अनुरक्षण और प्रचालन अधिकारियों के कार्यों के बारे में शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पिछले तीन वर्षों का सर्किलवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान इस में किस कर्मचारी अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो उसका सर्किलवार ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-कौन से सुधारात्मक उपाय किये गये हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

टेलीफोन उपभोक्ताओं के परिसरों में एक पृथक टेलीफोन मीटर का लगाया जाना

2551 श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार टेलीफोन उपभोक्ताओं के परिसरों में एक पृथक टेलीफोन मीटर लगाने के बारे में विचार कर रही है जिससे कि उपभोक्ताओं को भविष्य में एक तरफा मीटर रीडिंग में कुछ संरक्षण मिल सके ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) इसे तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य नहीं पाया गया।

Opening of P.C.Os and STD in Gujarat and Bihar

2552. SHRI RAMENDRA KUMAR YADAV "RAVI":

SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) what are the details of the schemes for opening P.C.Os and STD in big cities and rural areas of Gujarat and Bihar States in the coming year;

(b) what is the time frame fixed for implementing these schemes; and

(c) what percentage of population will be benefited after implementation of these schemes?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM) (a) Details of the schemes for opening local PCOs and STD PCOs are as per Statement I & II (*See* below). The targets fixed for opening public